[2008] 11 एस.सी.आर. 816

राजस्थान राज्य

बनाम

गजेन्द्र सिंह

(आपराधिक अपील संख्या 1217, 2008)

4 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.]

सजा/दंड - दोषसिद्धि यूएलएस 376 /पीसी - ट्रायल कोर्ट दस साल की सजा दे रहा है आर1 - उच्च न्यायालय द्वारा सजा को घटाकर पांच साल (निर्धारित न्यूनतम से कम) कर दिया गया - का औचित्य - माना गया: धारा का प्रावधान। 376/पीसी केवल 'पर्याप्त और विशेष कारणों' को दर्ज करने पर अदालत को निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा को कम करने की अनुमति देता है - उच्च न्यायालय की ओर से ऐसे कारणों को दर्ज करने में विफलता, सजा को कम करने की गारंटी नहीं देती है - आपराधिक कानून का पालन करता है सजा में आनुपातिकता का सिद्धांत -अपराध की प्रकृति और तरीके को ध्यान में रखते हुए उचित सजा देना अदालत का कर्तव्य है -अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी - सजा को संशोधित कर सात साल यानी न्यूनतम कर दिया गया है निर्धारित - दंड संहिता, 1860 - एस. 376 परंतुक.

शब्द और वाक्यांश - 'बलात्कार' - आईपीसी के संदर्भ में अर्थ।

प्रतिवादी पर आईपीसी की धारा 376, 323 और 341 के तहत मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रतिवादी ने सज़ा कम करने की प्रार्थना करते हुए अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने, हालांकि नोट किया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत न्यूनतम सजा सात साल है, फिर भी धारा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सजा को घटाकर पांच साल कर दिया गया, जिससे अदालत को सजा को निर्धारित न्यूनतम से कम करने की अनुमति मिल गई। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 उच्च न्यायालय द्वारा सज़ा को निर्धारित न्यूनतम से कम करना उचित नहीं था। प्रतिवादी को कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। सजा को कम करने के विवेक का प्रयोग करने के लिए वैधानिक आवश्यकता यह है कि न्यायालय को फैसले में "पर्याप्त और विशेष कारण" दर्ज करने होंगे, न कि काल्पनिक कारण जो न्यायालय को निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने की अनुमति देंगे। कारण न केवल पर्याप्त होना चाहिए बल्कि विशेष भी होना चाहिए। क्या पर्याप्त और विशेष है यह कई कारकों पर निर्भर करेगा और कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला इंगित नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम सज़ा से हटने के कारणों को दर्ज करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट पर जो बात लागू होती है, वह उच्च न्यायालय पर भी समान रूप से लागू होती है। कानून में पर्याप्त और विशेष कारणों की आवश्यकता संचयी है। उच्च न्यायालय ने सज़ा कम करने के लिए कोई पर्याप्त और विशेष कारण तो दूर, कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है। [पैरा 23, 24 और 25]

1.2 समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति को खत्म करना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवस्था" की इमारत की आधारशिला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां दया के साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं। प्रासंगिक तथ्य जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। [पैरा 12]

1.3 प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली न्यायसंगत और उचित सजा का निर्णय लेने के लिए, जिन गंभीर और कम करने वाले कारकों और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उन्हें निम्न के आधार पर नाजुक ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियाँ। [पैरा 16]

***डेनिस काउंसिल एमसीजीऑथा बनाम कैलिफोर्निया राज्य:* 402 यूएस 183: 28 एल.डी. 2डी 711 - संदर्भित।**

1.4 आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह

आम तौर पर प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने में न्यायाधीश को कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है, 'संभवतः ऐसे वाक्यों को अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोषीता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सज़ा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में वाक्य बड़े पैमाने पर अन्य विचारों से निर्धारित होते हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो किसी सजा को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती हैं। कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, तो कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी। अनिवार्य रूप से ये विचार सज़ा के आधार के रूप में ;ust रेगिस्तान से विचलन का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करते हैं जो गंभीर और व्यापक हैं। लेकिन वास्तव में, उन विचारों के अलावा जो अपराध के अनुपात से बाहर होने पर सज़ा को अनुचित बनाते हैं, समान रूप से अनुपातहीन सज़ा के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं। [पैरा 14 और 15]

1.5 कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा देना वास्तव में एक निरर्थक प्रयास हो सकता है। अपराध का सामाजिक प्रभाव, उदा. जहां यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों, डकैती, अपहरण, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, राजद्रोह और नैतिक अधमता या नैतिक अपराध से जुड़े अन्य अपराधों पर निर्भर करता है, जिनका सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता होती है। . ऐसे अपराधों के संबंध में कम सजाएं देने या केवल समय बीतने के कारण बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी उदार रवैया लंबे समय में परिणामी रूप से प्रतिकूल होगा और सामाजिक हित के खिलाफ होगा, जिसकी देखभाल करने की जरूरत है और अंतर्निहित निवारक स्ट्रिंग द्वारा इसे मजबूत किया जाना चाहिए। सजा प्रणाली में. [पैरा 18]

1.6 अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कमजोर होगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया या किया गया आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। [पैरा 13]

महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य **1987 (2) एससीआर 710;** *सेवक पेरुमल आदि बनाम तमिलनाडु राज्य* **एआईआर 1991 एससी 1463;** *धनंजय चटर्जी बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यूबी* **1994 (2) एससीसी 220;** *रावजीव. राजस्थान राज्य*, **1996 (2) एससीसी 175;** *मध्य प्रदेश*

राज्य बनाम घनश्याम सिंह **2003(8) एससीसी 13;** *मध्य प्रदेश राज्य बनाम बब्बू बरकरे उर्फ दलप सिंह* **2005 (5) धारा 413 - पर आधारित।**

स्टीफन 9वें संस्करण द्वारा "आपराधिक कानून", पृष्ठ 262; **'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस'** खंड 4, पृष्ठ 1356; हैल्सबरीज़ स्टैट्यूट्स ऑफ़ इंग्लैंड एंड वेल्स (चौथा संस्करण) खंड 12; फ्रीडमैन द्वारा 'लॉ इन चैंजिंग सोसाइटी' का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

1987 (2) एससीआर 710	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 12**
एआईआर 1991 एससी 1463	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 13**
402 यूएस 183: 28 एलओ। 2डी 711 का उल्लेख है।		**पैरा 16**
1994 (2) एससीसी 220	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 19**
1996 (2) एससीसी 175	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 20**
2003(8) एससीसी 13	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 21**
2005 (5) एससीसी 413	**पर भरोसा किया गया।**	**पैरा 21**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1217 / 2008,

2002 की एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 1105 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, बी जयपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.5.2006 से

अपीलकर्ता के लिए मधुरिमा टाटिया और अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का फैसला **अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा सुनाया गया। 1.अनुमति दी गई।

2. चूंकि, इस अपील में शामिल एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने सजा को कम करने में सही था, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी पर लगाया था, तथ्यात्मक पहलुओं का विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है।

3. प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 376, 323 और 341 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। उपरोक्त तीन अपराधों के लिए उन्हें क्रमशः 10 साल, छह महीने और छह

महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ जुर्माना लगाया गया।

5. प्रतिवादी ने सत्र वाद संख्या 30, 2002 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया उच्च न्यायालय के अनुसार धारा 376 आईपीसी से संबंधित अपराध के लिए सजा को घटाकर पांच साल के कठोर कारावास की अवधि तक कर दिया जाएगा और धारा 341 आईपीसी के मामले में छह महीने के साधारण कारावास की सजा को घटाकर एक महीने के साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। , वही अधिकतम सजा थी.

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी ने दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि केवल सजा कम करने की प्रार्थना की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 की उपधारा (1) के तहत, न्यूनतम सजा सात साल है, लेकिन यह प्रावधान के अधीन है कि अदालत "पर्याप्त और विशेष कारणों" के लिए कारावास की सजा दे सकती है। सात वर्ष से कम की शर्तें. बिना कोई कारण बताए, उच्च न्यायालय ने माना कि यह एक ऐसा मामला था जहां अदालत को न्यूनतम निर्धारित सजा से कम सजा देने की अनुमति देने वाला प्रावधान लागू था।

7. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील - राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सजा कम करने का निर्देश देने के लिए कोई कारण या आधार भी नहीं बताया है।

8. नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

9. जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विचारों की उचित सजा और स्वीकार्यता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 376 से संबंधित अपराधों के लिए निर्धारित सजाएं आजीवन कारावास या 10 साल की अवधि तक हैं, लेकिन सात साल से कम नहीं होनी चाहिए जब तक कि अदालत द्वारा कम सजा देने के लिए विशेष और पर्याप्त कारण न बताए जाएं।

10. बलात्कार का अपराध आईपीसी के अध्याय XVI में आता है। यह मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध है। उस अध्याय में, 'यौन अपराध' के लिए एक अलग शीर्षक है, जिसमें धारा 375, 376, 376-ए, 376-बी, 376-सी और 376-क्यू शामिल हैं। 'बलात्कार' को धारा 375 में परिभाषित किया गया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा धारा 375 और 376 को काफी हद तक बदल दिया गया है, और

नए अधिनियम द्वारा कई नई धाराएं पेश की गईं, यानी 376- ए, 376- बी, 376•सी और 376-डी। यह तथ्य कि व्यापक बदलाव पेश किए गए, बलात्कार के अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाने की विधायी मंशा को दर्शाता है, जो एक महिला की गरिमा को प्रभावित करता है। बलात्कार का अपराध अपने सरल शब्दों में 'किसी महिला की सहमति के बिना, बलपूर्वक, भय या धोखाधड़ी द्वारा उसका बलात्कार करना', या 'किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसका शारीरिक संबंध बनाना' है। 'बलात्कार' या 'रैप्टस' तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है (कं. लिट. 123-बी); या जैसा कि अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त किया गया है, 'बलात्कार किसी भी महिला का, उसकी इच्छा के विरुद्ध, विशेष वर्ष से अधिक उम्र का शारीरिक संबंध है; या उस उम्र से कम उम्र की महिला बच्चे की, उसकी इच्छा से या उसके विरुद्ध' (हेल पीसी 628)। बलात्कार के अभियोग में आवश्यक शब्द हैं रेपुइट और कार्नलिटर कॉग्रियोविट; लेकिन कार्नलिटर कॉग्नोविट, और न ही रैपुइट शब्द के बिना कोई अन्य परिवाद, बलात्कार को व्यक्त करने के लिए कानूनी अर्थ में पर्याप्त नहीं है; 1 माननीय 6, 1ए, 9 एड. 4, 26.ए (हेल पीसी 628), इन। बलात्कार का अपराध, 'शारीरिक ज्ञान' का अर्थ है पीढ़ी के पुरुष अंग द्वारा कथित रूप से जाने जाने वाले अंग की थोड़ी सी भी डिग्री तक प्रवेश (स्टीफन का "आपराधिक कानून" 9वां संस्करण। पृष्ठ 262)। 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस' (खंड 4, पृष्ठ 1356) में कहा गया है ".....थोड़ा सा भी प्रवेश पर्याप्त है और उत्सर्जन अनावश्यक है"। आईडी हैल्सबरी की स्टैट्स यूट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (चौथा संस्करण) खंड 12 में कहा गया है कि प्रवेश की थोड़ी सी डिग्री भी संभोग को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह हर तरह से एक महिला के निजी व्यक्तित्व की हिंसा के साथ उल्लंघन है। अपराध की प्रकृति से ही यह सर्वोच्च कोटि का घृणित कार्य है।

11. शारीरिक घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक घाव हमेशा बना रहेगा। जब एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो जो कुछ किया जाता है वह केवल शारीरिक चोट नहीं होती है, बल्कि कुछ मृत्युहीन शर्म की गहरी भावना होती है। अपराधी पीड़िता से उसकी सबसे मूल्यवान और अमूल्य संपत्ति यानी गरिमा छीन लेता है।

12. कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। लोगों के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक आवश्यक कार्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निस्संदेह, एक अंतर-सांस्कृतिक संघर्ष है जहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की

सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवस्था" की इमारत की आधारशिला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्रीडमैन ने अपने "लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी" में कहा कि, "आपराधिक कानून की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी इसे समाज की सामाजिक चेतना का निर्णायक प्रतिबिंब होना चाहिए"। इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां दया से संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं। प्रासंगिक तथ्य जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उदाहरण के लिए, गहरी आपसी और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई हत्या के लिए मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन एक संगठित अपराध या निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्याओं के निवारण के लिए मौत की सजा देने की आवश्यकता होगी। महेश बनाम एमपी राज्य [(1987) 2 एससीआर 710] में, इस न्यायालय ने मौत की सजा को कम करने से इनकार करते हुए इस प्रकार कहा:

> "ऐसे सबूतों और ऐसे क्रूर कृत्यों का सामना करने पर आरोपी को कानून के अत्यधिक दंड से बचने की अनुमति देना न्याय का मजाक होगा। आरोपी को कम सजा देना देश की न्याय प्रणाली को संदिग्ध बनाना होगा। आम आदमी का अदालतों पर से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे मामलों में, वह सुधारात्मक शब्दजाल की तुलना में निवारण की भाषा को अधिक समझता और सराहता है।"

13. इसलिए, अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया या किया गया आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। *सेवका पेरुमल आदि बनाम तमिलनाडु राज्य* मामले में इस अदालत ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया था। (AIR 1991 SC 1463)।

14. आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण

विवेक की अनुमति देता है, संभवतः ऐसे वाक्यों की अनुमति देता है जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोषीता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सज़ा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में वाक्य बड़े पैमाने पर अन्य विचारों से निर्धारित होते हैं। कभी-कभी यह "अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो किसी सजा को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती हैं। कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी-कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी। अनिवार्य रूप से ये विचार रेगिस्तान से विचलन का कारण बनते हैं क्योंकि सज़ा का आधार बनाना और स्पष्ट अन्याय के ऐसे मामले बनाना जो गंभीर और व्यापक हों।

15. अपराध और सज़ा के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया जाता है, और ग़लत धारणाओं के बावजूद, यह वाक्यों के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। अब भी एक भी गंभीर उल्लंघन के लिए कठोर सज़ाएं दी जाती हैं। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम गंभीरता के दंड से कम की सजा को सहनशीलता का एक उपाय माना जाता है जो अनुचित और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में, उन विचारों के अलावा जो अपराध के अनुपात से बाहर होने पर सज़ा को अनुचित बनाते हैं, समान रूप से अनुपातहीन सज़ा के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं।

16. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली न्यायसंगत और उचित सजा का निर्णय लेने के लिए, जिन गंभीर और कम करने वाले कारकों और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उन पर नाजुक ढंग से विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया गया। संतुलन बनाने का ऐसा कार्य वास्तव में एक कठिन कार्य है। इसे *डेनिस काउंसिल एमसीजीडौथा बनाम कैलिफोर्निया राज्य*: 402 यूएस 183: 28 एल.डी. मामले में बहुत उपयुक्त रूप से इंगित किया गया है। 2डी 711 कि फुलप्रूफ प्रकृति का कोई भी फार्मूला संभव नहीं है जो अपराध की गंभीरता को प्रभावित करने वाली अनंत परिस्थितियों में उचित और उचित सजा निर्धारित करने में उचित मानदंड प्रदान कर सके। किसी भी अचूक फार्मूले के अभाव में, जो अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का सही आकलन करने के लिए उचित मानदंड के लिए कोई आधार प्रदान कर सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में विवेकाधीन निर्णय ही एकमात्र तरीका है जिससे ऐसा निर्णय न्यायसंगत हो सकता है। विशिष्ट।

17. इसका उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को उचित सजा देकर कानून द्वारा घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना होना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि

अदालतें सजा प्रणाली का संचालन करेंगी ताकि ऐसी सजा दी जा सके जो समाज की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित करे और सजा प्रक्रिया को सख्त होना चाहिए जहां यह होना चाहिए।

18. कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा देना वास्तव में एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। अपराध का सामाजिक प्रभाव, उदा. जहां यह महिलाओं के खिलाफ अपराध, डकैती, अपहरण, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, राजद्रोह और नैतिक अधमता या नैतिक अपराध से जुड़े अन्य अपराध से संबंधित है, जिनका सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे अपराधों के संबंध में कम सजा देने या केवल समय व्यतीत होने के आधार पर बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी उदार रवैया लंबे समय में परिणाम-आधारित प्रतिकूल होगा और सामाजिक हित के खिलाफ होगा, जिसकी सजा प्रणाली में अंतर्निहित प्रतिरोध की देखभाल करने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

19. धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। (1994 (2) एससीसी 220), इस न्यायालय ने देखा है कि आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है, जिससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और अंततः सिस्टम की साख कमजोर होकर न्याय को नुकसान पहुंचता है। उचित सज़ा देना वह तरीका है जिससे अदालत अपराधी के खिलाफ न्याय की समाज की पुकार का जवाब देती है। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के अनुरूप सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा दर्शा सकें। न्यायालय को उचित दंड देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को बल्कि अपराध के पीड़ित और समग्र समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

20. इसी तरह का विचार रावजी बनाम राजस्थान राज्य, (1996 (2) एससीसी 175) में भी व्यक्त किया गया है। उक्त मामले में यह माना गया है कि यह अपराध की प्रकृति और गंभीरता है, लेकिन अपराधी नहीं, जो एक आपराधिक मुकदमे में उचित सजा पर विचार करने के लिए आवश्यक है। यदि उस अपराध के लिए उचित दंड नहीं दिया गया, जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ, बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया गया है, जिससे अपराधी और पीड़ित संबंधित है, तो अदालत अपने कर्तव्य में असफल होगी। द. किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उस अत्याचार और क्रूरता के अनुरूप होनी चाहिए जिसके साथ अपराध किया गया है, अपराध की विशालता सार्वजनिक घृणा की गारंटी देती है और इसे "समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए" अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए"।

21. इन पहलुओं को मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह (2003(8) एससीसी 13), और मध्य प्रदेश राज्य बनाम बब्बू बरकरे उर्फ ओलाप सिंह (2005 (5) एससीसी 413) में विस्तृत किया गया है।

22. उप-धारा (1) और (2) दोनों के मामलों में न्यायालय के पास 'पर्याप्त और विशेष कारणों' से निर्धारित न्यूनतम से कम कारावास की सजा देने का विवेक है। यदि न्यायालय फैसले में ऐसे कारणों का उल्लेख नहीं करता है तो निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

23. सजा कम करने के विवेक का प्रयोग करने के लिए वैधानिक आवश्यकता यह है कि न्यायालय को फैसले में "पर्याप्त और विशेष कारण" दर्ज करने होंगे, न कि काल्पनिक कारण जो न्यायालय को निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने की अनुमति देंगे। कारण न केवल पर्याप्त होना चाहिए बल्कि विशेष भी होना चाहिए। क्या पर्याप्त और विशेष है यह कई कारकों पर निर्भर करेगा और कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला इंगित नहीं किया जा सकता है। ,न्यूनतम सजा से हटने के कारणों को दर्ज करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट पर जो बात लागू होती है, वह उच्च न्यायालय पर भी समान रूप से लागू होती है।

24. जबड़े में पर्याप्त एवं विशेष कारणों की आवश्यकता संचयी होती है। उच्च न्यायालय ने सज़ा कम करने के लिए कोई पर्याप्त और विशेष कारण तो दूर, कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा सज़ा को निर्धारित न्यूनतम से कम करना उचित नहीं था।

25. जो ऊपर कहा गया है उसकी पृष्ठभूमि में, हम उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक रद्द करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में, प्रतिवादी को न्यूनतम सात साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

26. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।